

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 मार्च 2017—चैत्र 2, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2017

क्रमांक 8071-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 8 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 23 मार्च, 2017 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, २०१७

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ४ का संशोधन.
५. धारा ६ का संशोधन.
६. धारा ९ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

धारा १ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ (क्रमांक १२ सन् १९९९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.”;

(दो) उप धारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उप धारा अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(४) इस अधिनियम के उपबंध मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, २००१ (क्रमांक १० सन् २००१) के उपबंधों के अधीन लगाए गए वृक्षों को लागू नहीं होंगे.”.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग क) “आयुक्त” से अभिप्रेत है, संबंधित राजस्व संभाग का आयुक्त;”.

धारा ४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उप धारा (२) तथा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“(२) कलक्टर, ऐसे नियमों के अनुसार जो कि विहित किए जाएं, आवेदन की जांच करवाएगा तथा नब्बे दिन की कालावधि के भीतर आवेदन को मंजूर या नामंजूर करेगा :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा उस दशा में, उत्तराधिकार के सिवाय, मंजूर नहीं की जाएगी जहां किसी भी रीति में, भूमि में हक के अर्जन की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत न हो गई हो.

स्पष्टीकरण—हक के अर्जन की तारीख वह तारीख होगी जिसको कि हक का अंतरण लिखत द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है.

(३) किसी एक वर्ष में वृक्ष काटने की अनुज्ञा विनिर्दिष्ट वृक्षों की उतनी संख्या तक ही सीमित होगी जिससे भूमि स्वामी धन के रूप में किसी एक वर्ष में दस लाख रुपये से अनधिक उतनी रकम प्राप्त कर सके जो कि कलक्टर द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझी जाए :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कलक्टर, आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, किसी एक वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के लिए अनुज्ञा दे सकेगा.”.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उप धारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धारा स्थापित की जाए, धारा ६ का संशोधन.
अर्थात् :—

“(१) भूमिस्वामी को देय प्रतिफल की रकम, भूमिस्वामी के खाते में, किसी अनुसूचित बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की किसी भी शाखा में, निक्षिप्त की जाएगी.”

६. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उप धारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धारा स्थापित की जाए, धारा ९ का संशोधन.
अर्थात् :—

“(२) उपधारा (१) के अधीन कार्रवाई करने का आधार गठित करने वाले किन्हीं विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकड़ी का अभिग्रहण कर लिया जाएगा और वह राज्य सरकार को राजसात हो जाएगी :

परन्तु यदि भूमिस्वामी के प्रति कोई षड़यंत्र, कपट या छल किया जाता है तो इस प्रकार राजसात लकड़ी के विक्रय आगम, उस आपराधिक मामले के निपटारे के पश्चात्, कलक्टर के आदेश के अधीन भूमिस्वामी को दिए जाएंगे.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ (क्रमांक १२ सन् १९९९) की धारा ४ में यह उपबंध है कि किसी आदिम जनजाति से संबंध रखने वाला कोई भूमिस्वामी, किसी एक वर्ष में, कलक्टर की अनुज्ञा से उसकी भूमि पर खड़े पचास हजार रुपये तक की लागत के वृक्षों को काट सकता है, जो कि विशेष परिस्थितियों में दो लाख रुपये की सीमा तक बढ़ाई जा सकती है। परन्तु वर्ष १९९९ से अभी तक इमारती लकड़ी की कीमत में कई गुना वृद्धि हुई है और आदिम जनजाति से संबंध रखने वाले भूमिस्वामी की मूलभूत आवश्यकताएं भी सारवान रूप में परिवर्तित हुई हैं। अतएव, इस परिवर्तित परिस्थिति के अधीन वृक्षों को काटने के लिए धन संबंधी सीमा को पुनरीक्षित किया जाना अत्यावश्यक है। आदिम जनजाति से संबंध रखने वाले भूमिस्वामियों द्वारा अनुभव की जा रही कुछ कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से अधिनियम के कतिपय अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना भी प्रस्तावित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख २२ मार्च, २०१७

लाल सिंह आर्य

भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-४ द्वारा भू-स्वामी को पेड़ काटने की अनुज्ञा प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन को निर्धारित अवधि में मंजूर या नामंजूर किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं। उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा।

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा.